

### सार समाचार

#### साहित्य अकादमी अवार्ड 2018: 24 भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा, चित्रा मुद्दल को हिंदी में मिला अवार्ड

नई दिल्ली। हिन्दी की प्रसिद्ध  
लेखिका चित्रा मुद्दल समेत 24 लेखकों  
को बुधवार को वर्ष 2018 के लिए  
साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा  
की गई। उद्द में साहित्य अकादमी का  
अवार्ड रहमान अब्बास और अंग्रेजी में  
अनीस सलीम को मिला। अकादमी के  
अध्यक्ष चंद्रशेखर कम्बार की अध्यक्षता में  
निर्णायक समिति ने इन पुरस्कारों को  
मंजुरी दी। हिंदी लेखिका चित्रा मुद्दल  
को उनके उपन्यास नाला सोपारा पोस्ट  
बॉक्स नं. 203 को पुरस्कार के लिए  
चुना गया। पुरस्कार में प्रत्येक विजेता को  
एक-एक लाख रुपये, एक प्रशस्ति पत्र  
और प्रतीक चिह्न दिए जाएंगे। ये  
पुरस्कार 29 जनवरी को राजधानी में दिए  
जाएंगे।

#### बंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में धमाका, एक वैज्ञानिक की मौत 3 गंभीर रूप से जखमी

दिल्ली नई दिल्ली। बंगलुरु में बुधवार  
को प्रयोग के दौरान एक संदिग्ध  
सिलिंडर विस्फोट हो गया। पुलिस के  
मुताबिक, इस विस्फोट में 32 वर्षीय के  
वैज्ञानिक की मौत हो गई। उन्होंने बताया  
कि एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी के चार  
टेक्नीशियन कुछ प्रयोग कर रहे थे कि  
दोपहर 2 बजेकर 20 मिनट पर अचानक  
धमाका हो गया। इस दौरान, मौके पर ही  
मैसूर के रहनेवाले टेक्नीशियन मनोज की  
मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो  
गए हैं। घायलों के एक प्राइवेट अस्पताल  
में भर्ती कराया गया है जहां उन सभी की  
हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि,  
किस तरह का विस्फोट था और उसके  
क्या कारण थे इसका पता लगाया जाना  
अभी बाकी है। लेकिन, ऐसा माना जा  
रहा है कि यह घटना सिलिंडर में रखी  
गई गैस के चलते हुई है। असिस्टेंट  
कमिश्नर ऑफ पुलिस निरंजन राज उसने  
पिटीआई को बताया कि स्टार्ट अप  
कंपनी सुपरवेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट  
लिमिटेड का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ  
साइंस के साथ शोध के लिए प्रयोग पर  
टाईअप है। उन्होंने कहा- फरेंसिक  
एक्सपर्ट अब ये बताएंगे कि वास्तव में  
इस घटना का क्या वजह है लेकिन ऐसा  
लगता है कि यह सिलिंडर ब्लास्ट है।

#### तोहफा: अब इन ट्रेनों में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी 6 और सीटें

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे (IN-  
DIAN RAILWAYS) ने महिलाओं के  
लिए सीटगत दी है। अब राजधानी,  
दुरंतो और सभी एयर कंडीशंड ट्रेनों के  
AC-3टीयर में महिलाओं के लिए 6  
सीटें आरक्षित होंगी। यह आरक्षण वरिष्ठ  
नागरिकों, 45 वर्ष की आयु से अधिक  
की महिला यात्रियों और गर्भवती  
महिलाओं के लिए, ए-3 टियर में हर  
बोगी में आर्वाटिड नीचे की 4 सीटों से  
संयुक्त आरक्षण के अलावा है। रेलवे  
पहले से ही हर मेला/एक्सप्रेस ट्रेनों में  
महिला यात्रियों को उनकी उम्र, अकेले  
यात्रा करने या समूह में यात्रा करने के  
आधार पर स्लीपर क्लास की 6 बर्थ का  
आरक्षण भी देता है।

सख्ती: विदेश यात्रा करने  
वालों पर है आयकर विभाग की  
नजर, जानिए क्यों  
इसके अतिरिक्त गरीब रथ एक्सप्रेस  
ट्रेन के 3 एसी में हर ट्रेन में महिलाओं के  
लिए 6 सीटें भी आरक्षित होती हैं। हर  
ट्रेन के स्लीपर क्लास में वरिष्ठ नागरिकों,  
45 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वाली  
महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के  
लिए नीचे की छह सीटें और AC 3  
तथा AC 2 टियर क्लास में हर बोगी में  
नीचे की तीन सीटें संयुक्त रूप से  
आरक्षित होती हैं।



असम के कामरूप जिला स्थित गोरोंमारी में बुधवार को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग सामग्री लेकर विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए नाव से रवाना होते चुनाव अधिकारी।

### बुलंदशहर हिंसा की FIR ने खोली पोल, मुठभेड़ करने वाली पुलिस नहीं चला सकी गोली

मुजफ्फरनगर। यूपी के बुलंदशहर  
(Bulandshahr) में हुई हिंसा में  
पुलिस की पोल पुलिस द्वारा ही दर्ज  
कराई गई एफआईआर ही खोल रही है।  
एफआईआर से साफ है कि उपद्रव के  
दौरान थियर पुलिसकर्मियों के पास एके-  
47 जैसे अत्याधुनिक असलहों और उन्हें  
चलाने में प्रशिक्षित 18 से अधिक युवा  
पुलिसकर्मियों भी थे। लेकिन उनमें से कोई  
भी फायरिंग का साहस नहीं कर सका।  
सिर्फ एक होमगार्ड के ही हवाई फायर  
किए जाने का उल्लेख है।  
स्थाना में सोमवार को हुए बवाल के  
दौरान हथियारों से लैस पुलिस लिखा-  
पढ़ी में गोली तक चलाने का उल्लेख नहीं  
कर पाई।  
उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र की ओर से  
दर्ज कराई गई एफआईआर में उल्लेख  
किया गया है कि वह इस्मेक्टर सुबोध  
कुमार सिंह के साथ घटनास्थल पर महाव  
गांव पहुंचे थे। उनके साथ एचसीपी, चार  
सिपाही, तीन होमगार्ड व एक हेड स्टर  
का चालक यानी कुल 12 पुलिसकर्मियों  
थे। चिंगरावटी पुलिस चौकी का फोर्स  
पहले से मौके पर होगा।  
एफआईआर में सीओ स्थाना और  
एसडीएम स्थाना के मौके पर होने का  
उल्लेख है। सीओ के हमराह दो तीन  
पुलिसकर्मियों भी मौके पर रहे होंगे, जिनमें  
एक के पास आटोमेटिक हथियार होगा।  
एसडीएम का सुरक्षाकर्मियों भी मौके पर  
था। भीड़ द्वारा जमकर पथराव करने,



चौकी पर सरकारी वाहनों में आगजनी  
करने, चौकी के कमरे में जान बचाने को  
घुसे सीओ स्थाना को जलाने की नीयत  
से आग लगाने, इस्मेक्टर सुबोध कुमार  
को गोली लगने आदि का उल्लेख तो  
किया गया है।  
एके-47, पिस्टल लिए  
पुलिसकर्मियों द्वारा एक भी गोली चलाने  
का उल्लेख नहीं किया गया है।  
इसके बाद मौके पर सीओ के  
बुलावे पर शिकारपुर सीओ, औरंगाबाद,  
बोबीनगर, नरसेना, खानपुर और  
मुख्यालय से स्वाट टीम के पहुंचने का  
उल्लेख है।  
इनके पहुंचने के बाद ही दरवाजा  
तोड़कर सीओ स्थाना को चौकी से  
निकालने और घायल हुए इस्मेक्टर  
सुबोध कुमार को लखावटी सीएचसी पर  
पहुंचाने का उल्लेख किया गया है।  
इस्मेक्टर के गोली लगने और सीओ  
को चौकी के कमरे होने पर भी चौकी में  
आग लगाने के बाद भी पुलिसकर्मियों  
द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग नहीं करने से  
पुलिस की अक्षमता सामने आई है।

### पांचवीं कक्षा की छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़ आरोपी सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार

नई दिल्ली एजेंसी। उत्तम नगर इलाके के एक नामी पब्लिक स्कूल में सुरक्षा गार्ड ने पांचवीं कक्षा छात्रा से छेड़छाड़ की। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी 22 वर्षीय  
विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद विपिन को मौके पर  
पकड़ लिया गया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पाँचसो समेत अन्य  
धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस मामले को जांच कर रही है। छानबीन में पता चला है  
कि 11 साल की पीड़ित छात्रा सपरिवार उत्तम नगर में रहती है। उसके पिता कार  
मैकेनिक हैं। पीड़ित बच्ची एक पब्लिक स्कूल में पांचवीं कक्षा की छात्रा है। बच्ची के  
पिता ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार दोपहर में बच्ची को स्कूल में लेने गए  
थे। जहाँ उनकी बेटी ने बताया कि एक गार्ड उसे दूसरे बाथरूम में ले गया और उससे  
अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की। इस पर बच्ची ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर  
स्कूल के टीचर और अन्य लोग मौके पर जमा हो गए और मामले की सूचना पुलिस  
को दी गई।

### फर्जी बिलों पर यात्रा भ्रजा लेने का है मामला

## पूर्व सांसद को तीन साल की कैद

रपए का जुर्माना भी किया है।  
पूर्व सांसद ने सजा सुनाए जाने के  
दौरान अदालत से नरमी बरतने की मांग  
की और कहा कि वे काफी उम्रदराज हो  
चुके हैं। उन्हें कई तरह की बीमारियाँ हैं।  
साथ ही अपने परिवार की देखभाल  
करनी है। उन्हें कम से कम सजा दी  
जाए। उन्होंने अदालत से यह भी कहा  
कि वह इस फैसले पर हाईकोर्ट में अपील  
करेंगे।  
तब तक के लिए जमानत दे दी  
जाए। अदालत ने उनकी बात मानते हुए

उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। पूर्व  
सांसद लियाना मिजोरम से दो बार  
राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं।  
पूर्व सांसद ने हवाई टिकटों में  
हेराफेरी कर 10.30 लाख से ज्यादा रपए  
राज्यसभा सचिवालय से लिए थे।  
अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी,  
फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज पेश करने व  
भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 29  
नवम्बर को दोषी ठहराया था। उसने कहा  
कि अभियुक्त सांसद ने वर्ष 2012-13  
के दौरान अपने कंप्यूटर से ई टिकट में

### तेलंगाना: कांग्रेस नेता रेवनाथ रेड्डी की गिरफ्तारी पर भड़का चुनाव आयोग, एसपी को हटाया

एजेंसी नई दिल्ली। तेलंगाना में  
कांग्रेस नेता ए. रेवनाथ रेड्डी की गिरफ्तारी  
को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को  
विकराबाद जिले के एसपी को हटाने का  
आदेश दिया है।  
पोल पैनल के सूत्रों के मुताबिक,  
पुलिस ऑब्ज़र्वर ने रेवनाथ रेड्डी को  
हिरासत में लिए जाने को 'अनुचित'  
माना।  
चुनाव अधिकारी ने बताया- चुनाव  
आयोग ने विकराबाद के एसपी टी.  
अन्नपूर्णा को वहाँ से हटाने और तत्काल  
प्रभाव से नए एसपी अविनाश मोहंती को

नया एसपी नियुक्त करने का फैसला  
किया है।  
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है  
कि अन्नपूर्णा की ड्यूटी पुलिस मुख्यालय  
में लगाई जाए और उसे चुनाव से  
संबंधित कोई कार्य नहीं सौंपे जाए।  
चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर नजर  
रखने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से  
पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।  
मंगलवार तड़के विकराबाद पुलिस ने  
तेलंगाना कांग्रेस समिति के वरिष्ठ  
प्रेसिडेंट रेड्डी को कानून व्यवस्था का  
हवाला देते हुए प्रिवेंटिव कस्टडी में ले

लिया था।  
रेड्डी की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री के.  
चंद्रशेखर राव की कोर्टगल में बैठक से  
ठीक पहले की गई।  
रेवनाथ ने कोर्टगल बंद का आह्वान  
किया था और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा  
ता कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री  
के कार्यक्रम का विरोध करें।  
हालांकि, सीएम चंद्रशेखर राव की  
कोसिंगी विधानसभा में बैठक खत्म होने  
के बाद रेवनाथ रेड्डी को छोड़ दिया गया।  
तेलंगाना में 7 दिसंबर को चुनाव होना  
है।

### यूपी भर्ती परीक्षाएं: राज्य से बाहर छपेगा पेपर, गड़बड़ियां रोकने को लिए गए ये 10 बड़े फैसले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने  
राज्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में  
गड़बड़ियां रोकने के लिए नीति तय कर  
दी है। पेपर लोक से बचने के लिए यूपी  
से बाहर की प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर  
छपना अनिवार्य होगा। प्रेस चारों ओर से  
सीसीटीवी कैमरों से घिरी हो। सुरक्षा के  
पूरे इंतजाम हों। साथ ही कोई काम या  
कर्मचारी आउटसोर्सिंग का न हो। बाहरी  
जर्मन को अदखल प्रतिकर्षित हो। मोबाइल  
फोन व कैमरा आदि ले जाने पर रोक  
हो।

1. रैडम बेसिस पर परीक्षा केंद्रों  
का आवंटन  
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव  
नियुक्ति एवं कार्मिक मुकूल सिंहल ने  
मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है।  
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि  
संदिहात्मक विद्यालयों और संस्थानों को  
भर्ती परीक्षा के लिए केंद्र न बनाया जाए।  
साथ ही रैडम बेसिस पर परीक्षा केंद्रों का  
आवंटन करें, जिससे एक ही स्थान के  
परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र पर बैठकर  
परीक्षा न दे सकें।  
2. कैमरे लगे परीक्षा केंद्रों में  
प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षा केंद्रों  
का चयन करने के लिए मानक तय किए  
हैं। इनके चयन में सावधानी जरूरी  
होगी। इसके चयन में जिला प्रशासन का  
योगदान लिया जाए। परीक्षा केंद्र के लिए  
यह अनिवार्य कर दिया गया है कि  
उसकी बाउंड्रीवाल हो और बंद करने  
वाला गेट लमा हो। परीक्षा केंद्र में सभी

परीक्षा कक्षाओं में प्रकाश और पंखों की  
समुचित व्यवस्था हो। सभी परीक्षा कक्षाओं  
में सीसीटीवी कैमरे लगे हों।  
सेना भर्ती में संधारणी करने वाले  
गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार  
3. पानी, शौचालयों और बिजली  
की अच्छी व्यवस्था  
फर्नीचर, पीने के पानी, शौचालयों  
और बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था हो।  
परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र रखने के लिए  
सीसीटीवी कैमरे युक्त एक अलग कक्ष  
हो।  
4. परीक्षार्थियों का सामान रखने  
की व्यवस्था हो  
परीक्षार्थियों के बैग, मोबाइल रखने  
की व्यवस्था हो। परीक्षा केंद्र का पिछला  
रिकार्ड देखा जाए। केंद्र पर तलाशी की  
व्यवस्था की जाए।  
5. महिलाओं की तलाशी  
महिलाएं लें  
महिलाओं के लिए महिलाएं ही  
तलाशी लें। परीक्षा केंद्र की बस स्टैंड,  
रेलवे स्टेशन आदि से दूरी, परीक्षार्थियों  
की बैठने की क्षमता, कार्मिकों की  
संख्या, सड़क की स्थिति जैसे मानकों  
का भी ध्यान रखा जाए।  
दारोगा बहाली परीक्षा रद्द करने से  
पटना हाईकोर्ट का इनाकार  
6. संयुक्त कमेटी करेगी  
परीक्षा केंद्रों का चयन संयुक्त कमेटी  
करेगी। परीक्षा केंद्रों (एबीसीडी) का  
निर्धारण डीएम की अध्यक्षता में कमेटी  
करेगी। जिसके सदस्य एसएसपी, उच्च  
शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के अधिकारी,  
एचआईसी के अधिकारी व डीआईओएस

सदस्य होंगे। कमेटी यह भी देखेगी कि  
केंद्र की दूरी ज्यादा न हो।  
7. परीक्षा के कक्ष निरीक्षकों को  
परीक्षा से एक दिन पहले कक्ष निरीक्षक  
नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा से कुछ समय  
पहले ही उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाएगी।  
8. पेपर का अतिरिक्त सेट रहे  
प्रश्नपत्र बनाते समय इस बात का  
ध्यान रखा जाए कि जरूरत पड़ने पर  
अतिरिक्त सेट उपलब्ध रहे। उत्तरों के  
विकल्प भी मल्टिपल सेट में रहें जिससे  
नकल की गुंजाइश से बचा जा सके।  
आबोकिटव टाइप प्रश्नपत्रों के संबंध में  
ओएमआर सीट की तीन प्रतियां रखी  
जाए जिससे एक प्रति सुरक्षित रखी जा  
सके और एक प्रति परीक्षार्थी को दी जा  
सके। कोषागार से परीक्षा केंद्र तक  
प्रश्नपत्र मजिस्ट्रेट व पुलिस सुरक्षा में भेजे  
जाए। स्टिल ट्रक में भेजे जाएं और उसमें  
डिजिटल लाक हो।  
9. आदेश की अन्य खास बातें  
परीक्षाओं की शुचिता बरतने के लिए  
प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में  
डीजीपी सहित संबंधित विभाग के प्रमुख  
सचिव की अध्यक्ष में कमेटी बनाई जाए।  
10. एजेंसी के चयन में खास  
सतर्कता बरती जाए  
यूपी लोक सेवा आयोग प्रयागराज  
और यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  
सहित सभी आयोगों और बोर्डों से कहा  
गया है कि परीक्षा कराने की एजेंसी के  
चयन में खास सतर्कता बरती जाए।  
संदिहात्मक एजेंसी को यह काम न सौंपा  
जाए।



इलाहाबाद : आगामी कुंभ मेले के मद्देनजर मेला क्षेत्र में दीवारों पर बनाई गई खूबसूरत रंग-बिरंगी पेंटिंग को निहारते हुए गुजरात एक साइकिल सवार।

## संपादकीय



सियासत की तल्लियों का ही नतीजा है कि आज सत्ताधारियों को उनका प्रत्येक विरोधी अथवा आलोचक अपना दुश्मन दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा विरोधियों के प्रति इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अमर्यादित हो रही है। लगता है कि सत्तापक्ष और विरोधी दल एक-दूसरे को लोकतंत्र का हिस्सा मान कर उनको स्वीकार करने के बजाए, उन्हें समाप्त करने की इच्छा रखते हैं, जो कि गलत है।

## सियासत में 'तल्लियों' की इंतहा

भारतवर्ष की सत्ता केंद्रित राजनीति संभवतः वर्तमान रूप में सबसे शर्मनाक दौर से गुजर रही है। पक्ष तथा विपक्ष एक-दूसरे से सहयोग करने के बजाए एक-दूसरे को नीचा दिखाने, अपमानित करने तथा पूरी तरह से परस्पर असहयोग का वातावरण पैदा करने में जुटे हुए हैं। चुनावी वादों को पूरा करने, देश को एक सूत्र में पिरोए रखने की कोशिशों और सामाजिक एकता बनाए रखने की आवश्यकताओं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे विषयों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिशों की जा रही है और ठीक इसके विपरीत अपने विरोधी दल और उसके नेताओं पर लांछन लगाने, देश की विकास संबंधी परियोजनाओं में बाधा डालने, किसी की उपलब्धि का दूसरे पक्ष द्वारा झूठा श्रेय लेने, राजनीति को शत-प्रतिशत मार्केटिंग के माध्यम से चमकाने जैसी कोशिशों परवान चढ़ रही हैं। वैसे तो हर आने वाला चुनाव पिछले चुनावों से अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। परंतु 2019 का चुनाव तो गोया पक्ष-विपक्ष दोनों ही के लिए करो या मरो जैसी स्थिति पैदा करने वाला होने जा रहा है। ऐसे तल्लय राजनीतिक वातावरण का सीधा नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ रहा है।

सवाल यह है कि राजनेताओं द्वारा आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? क्या इस विभाजनकारी राजनीति के अंजाम से नेता बेखबर हैं? क्या इन्हें इस बात का अहसास नहीं कि तल्लय सियासत का यह तरीका उन्हें छल-कपट, मक्कारी व मार्केटिंग तथा झूठे-सच्चे आरोपों व दावों-प्रतिदावों के माध्यम से शायद सत्ता तक तो पहुंचा दे परंतु इस तरीके से जनता के मध्य तथा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राजनीति की क्या छवि बन रही है उन्हें इसका भी अहसास है? जो भारतवर्ष अपनी शिष्टता, सौम्यता तथा नैतिकता के लिए जाना जाता था जिस देश में सैकड़ों ऐसे समर्पित राजनेता पैदा हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन सच्चाई, ईमानदारी तथा सदाचार के साथ राजनीति में गुजारा, आज वही राजनीति गाली-गालच, धक्का-मुक्की तथा अपने विरोधी दल को पूरी तरह से समाप्त करने जैसी धिनीनी कोशिशों का प्रयोग बन्कर रह गई है? और तल्लय सियासत की पराक्रांता तो यह है कि सांप्रदायिक व जातिगत दुर्भावना से पोषित इस अंधेरी सियासत के कई पैसेदार अब किसी निहत्थे, बेगुनाह, कमजोर व अकेले व्यक्ति के हत्थके समूह के पक्ष में खल कर खड़े होते नजर आने लगे हैं।

पिछले दिनों दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में निर्मित सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन अवसर पर एक भाषण दिया जो

वर्तमान तल्लय सियासत का जीता जागता सबूत था। मुझे नहीं लगता कि देश की किसी महत्वपूर्ण लोकहितकारी योजना के उद्घाटन के अवसर पर किसी जिम्मेदार नेता द्वारा ऐसा भाषण दिया गया होगा। कल्पना कीजिए कि यदि विदेशी मीडिया मनीष सिसोदिया के उस भाषण को जस का तस अपने-अपने देश में प्रसारित करे तो भारतीय राजनीति के लिए स्थिति कितनी शर्मनाक होगी। आमतौर पर उद्घाटन के समय योजना से संबंधित बातें की जाती हैं। उसके लाभ गिनाए जाते हैं या उसके तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। यदि किसी राज्य की योजना में केंद्र सरकार का भी सहयोग अथवा योगदान होता है तो उसकी सराहना की जाती है तथा केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि वहां सम्मानपूर्वक उपस्थित भी रहते हैं। परंतु दिल्ली के 154 मीटर ऊंचे सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन अवसर पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा किया गया यह ट्वीट दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के रिश्तों की तल्लयी को उजागर करने के लिए काफी था। सिसोदिया ने चार नवंबर को ट्वीट में लिखा कि 'सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाषण चल रहा था तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी मंच पर बोलत से हमला करने और सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ के महान कार्य में व्यस्त थे।' सिसोदिया का यह ट्वीट मनोज तिवारी के धक्का मुक्की व हाथापाई के उन प्रयासों के संदर्भ में आया जिसके द्वारा तिवारी उद्घाटन मंच पर आमंत्रित न होने के बावजूद मंच पर सम्मानपूर्ण स्थान चाह रहे थे। सिसोदिया ने तो अपने पूरे भाषण में इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की न केवल उदासीनता बल्कि नकारात्मकता का भी जो रहस्योद्घाटन किया वह बेहद चिंताजनक था।

सिसोदिया ने सार्वजनिक रूप से यह बताया कि किस प्रकार उनके अधिकारिण इस सिग्नेचर ब्रिज के पूरा होने से पूर्व होने वाली समीक्षा बैठकों में उन्हें यह बताया करते थे कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर इस पुल को पूरा नहीं होने देना चाहती। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि हमारे अधिकारियों को केंद्र द्वारा सीबीआई तक की धमकी दी गई। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पुल के निर्माण में एक इंच का सहयोग नहीं दिया। उनके भाषण में उस बात का भी जिक्र था किस प्रकार मेट्रो रेल के नोएडा सेक्शन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिल्ली के सीएम को आमंत्रित न किए जाने की परंपरा की शुरुआत की गई। और भी इस प्रकार के

कई आरोप मुख्यांमत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने अपने भाषणों में लगाए। यदि आप इनके भाषणों को गौर से सुनें व उनकी समीक्षा करें तो ऐसा महसूस होगा जैसे कि दो सरकारें नहीं बल्कि दो दुश्मन राज्य एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल ने तो यह भी कहा कि 'भाजपाईं स्ट्रेच्यू तथा मंदिर के निर्माण में व्यस्त हैं तो हम पुल, स्कूल और अस्पताल बना रहे हैं।

सियासत की इन्हीं तल्लियों का ही नतीजा है कि आज सत्ताधारियों को उनका प्रत्येक विरोधी अथवा आलोचक अपना दुश्मन दिखाई दे रहा है। विरोधियों को सीबीआई, आईटी तथा ईडी जैसे विभागों का भय दिखाया जा रहा है। विरोध जब ज्यादा प्रखर हो जाए तो उसे देशद्रोही, राष्ट्रविरोधी, अराजक, राष्ट्रविभाजक, हिंदू शत्रु और यहां तक कि पाक परसत तक बताया जा रहा है। इन परिस्थितियों में कोई भी महसूस कर सकता है कि भारतवर्ष ने तल्लय सियासत का ऐसा धिनीना दौर पहले भी कभी देखा है? राजनीति का यह निम्नतम स्तर आवाग को कहां ले जाएँगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। देश की राजनीति में पिछले कुछ सालों से कर्कशता व आक्रामकता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों द्वारा विरोधियों के प्रति इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, उपमाएं, तुलना आदि भी अमर्यादित हो रही हैं। ऐसा लगता है कि सत्तापक्ष और विरोधी दल एक दूसरे को लोकतंत्र का हिस्सा मान कर उनको स्वीकार करने के बजाए, उन्हें समाप्त करने की इच्छा रखते हैं। लोकतंत्र में स्वस्थ और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने अलावा किसी और दल की नीतियों को देश हित में नहीं मानता। यहां तक कि राजनीतिक के हाशिए पर पहुंच चुके वाम दल भी यही कहते हैं कि उनके अलावा कोई भी दल देश की समस्याओं को हल नहीं कर सकता।

तनवीर जाफरी  
(वरिष्ठ पत्रकार)

## विचार

## गोहत्या के नाम पर फिर गुंडागर्दी

बुलंदशहर में गोवंश मिलने के नाम पर जो कुछ हुआ, वह कानून की ध्वजियां उड़ाने के लिए काफी है। अब सवाल यह है कि यह सब कब तक चलेगा? गोहत्या के नाम पर जो कुछ हुआ है, वह अब बंद होना चाहिए। यह तभी होगा, जब सरकारें जिम्मेदारी को समझेंगी।



गोहत्या के नाम पर तथाकथित हिंदुवादी लोगों का आराजक रवेया फिर सामने आया है। बुलंदशहर में गोवंश के अवशेष मिलने पर सोमवार को बवाल हो गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। बवाल के दौरान एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। बुलंदशहर में सोमवार को गोकशी की अफवाह पर हुई हिंसा में इंसानियत, ईमान और अमन सब खाक हो गए। तीन गांवों के तकरीबन 400 लोग एक साथ आए और पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। जिले में हालात इस कदर भयावह हो गए कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया और जब तक कुछ समझा जाए, तब तक भीड़ ने एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मार डाला। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक अफवाह फैलाई जाती है, लोगों को उकसाया जाता है, दंगा भड़काया जाता है। भीड़ मरने-मारने पर उतारू हो जाती है और अफसर, सरकार सोती रहती है। यह सब सिर्फ गोवंशों की अफवाह पर हुआ। अब तक पुलिस या जांच एजेंसी को गोहत्या के सबूत तक नहीं मिले हैं। फिर भीड़ को क्या सूझा कि वह बवाल पैदा कर दे।

यकीनन, बुलंदशहर में जो कुछ हुआ, वह लचर कानून-व्यवस्था का ही परिणाम है। अब प्रशासनिक अफसरों से लेकर सरकार तक अपनी नाकामी पर पर्दा डालने में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज को मुख्य आरोपी बनाया है। एक के बाद एक लोगों की धरपकड़ हो रही है। पुलिस से जितना बन पड़ रहा है, वह गंभीर प्रतीत हो रही है, मगर सवाल यह है कि क्या यह सब पहली बार हो रहा है। समाज के प्रबुद्धजन के अलावा प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद गोहत्या के आरोप में भीड़ का बार-बार उत्यात मचाना कब बंद होगा। क्या भीड़ अब खुद को कानून से बड़ा मानने लगी है या फिर उनमें कानून का जरा भी डर नहीं रह गया है।

इस घटना ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि स्थानीय खुफिया एजेंसियां और पुलिस का तंत्र फेल साबित हो रहा है। यह हालात तब हैं जब सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा अनेक बार इनपुट दिया जा चुका है कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश हो रही है और मुजफ्फरनगर दंगे की तरह ही एक बार फिर से चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। बुलंदशहर में हुए इज्जतमा से पहले भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इस पुरे मामले में पुलिस की भूमिका भी कम संदिग्ध नहीं है। बुलंदशहर में जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह भीड़ से अकेले लड़ रहे थे, तब पूरा पुलिस अमला उन्हें छोड़ अपनी जान बचाने में लगा था। पुलिस का अचानक वहां से गायब होना कई सालों को जन्म दे रहा है। खैर, गोहत्या के नाम पर जो कुछ हुआ है, वह अब बंद होना चाहिए। यह तभी होगा, जब सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझेंगी।

## इंटरनेट की गिरफ्त में बचपन

सूचना तकनीक और इंटरनेट ने इस दुनिया के विकास में बड़ा योगदान दिया है लेकिन अब तेजी से इसके बड़े दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मसलन इसका तकनीक का गुलाम बनता जा रहा है। बच्चों का बचपन भी अब इंटरनेट की गिरफ्त में आ चुका है या यह कहें कि बच्चे भी अब तेजी से इंटरनेट की गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाजार ने बच्चों के लिए भी इंटरनेट पर इतना कुछ दे दिया है कि वह पढ़ने के अलावा अपना ज्यादातर समय इंटरनेट पर ही बिता रहे हैं। पिछले दिनों फ्रांस की संसद ने एक कानून बनाकर देश के प्राथमिक और जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यह कानून वर्तमान स्कूलों की प्रथा है कि सितंबर 2018 से लागू हो गया है। इसके बाद दुनियाभर में इस पर बहस शुरू हो गई है, कई लोग स्कूल में मोबाइल के फायदे गिना रहे हैं जबकि फ्रांस के युवा राष्ट्रपति एमैन्युएल मैक्रों ने विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टों को आधार बनाकर ही अपने देश में बच्चों के स्कूल में सेल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल खूद पेश किया और सांसदों से इसके लिए समर्थन मांगा।

फ्रांस जैसे विकसित देश के इस कदम से भारत में भी कुछ लोग ऐसी पाबंदी के कानून की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां स्कूलों में मोबाइल फोन के दुरुपयोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण से तैयार अल्टीमल वीडियो क्लिप से इंटरनेट संसार भरा पड़ा है। असल में कम उम्र के बच्चे क्लास में फोन लेकर बोर्ड और पुस्तकों के स्थान पर मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वे एक-दूसरे को मैसेज भेजकर बातें करते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर सक्रिय रहते हैं। इससे उनके सीखने और याद रखने की गति तो प्रभावित हो ही रही है, अब स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर हो रहा है। अब वे खेल के मैदान में परीना बहाने के बजाय आभासी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, इससे कम उम्र में ही उनमें मोटापा, आलस्य, आंखें कमजोर होना, याददाशर कमजोर होने जैसे प्रभाव भी दिखने लगे हैं। पहले बच्चे जिस गिनती, पढ़ाई, स्पेलिंग या तथ्य को अपनी स्मृति में रखते थे, अब वे सर्च इंजन की चाहत में उसे याद नहीं रखते, यहां तक की कई बच्चों को अपने घर का फोन नंबर तक याद नहीं रहता। ऐसे में अपने देश के स्कूलों में कम से कम भी आठवीं कक्षा तक मोबाइल प्रतिबंधित होना चाहिए।

अभी पिछले दिनों दिल्ली पुलिस और एम्स के बिहेवियर एडिक्शन ट्रेनिंग द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि स्कूलों में पढ़ने वाले हर पांच छात्र में से एक छात्र प्रोब्लेमेटिक इंटरनेट



पिछले दिनों दिल्ली पुलिस और एम्स के बिहेवियर एडिक्शन यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि स्कूलों में पढ़ने वाले हर पांच छात्र में से एक छात्र इंटरनेट की बुरी लत का शिकार है। इस तरह के सर्वे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक परिस्थिति में जरा भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन अब हमें ही सोचना होगा, क्योंकि सवाल हमारे बच्चों का है।

यूजर यानी पीआईयू का शिकार है। पीआईयू का अर्थ है कि हर पांच में से एक छात्र इंटरनेट की बुरी लत का शिकार है। इंटरनेट गेमिंग, सर्फिंग या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने इन युवाओं का इंटरनेट का क्रेज इनकी पढ़ाई, सोशल लाइफ व करियर को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सर्वे के मुताबिक 37 फीसदी छात्र मिजाज और पढ़ाई के प्रेशर से ध्यान हटाने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। इस सर्वे में दिल्ली के साउथ इस्ट डिस्ट्रिक्ट के 25 नामी स्कूलों के कुल 6291 छात्रों ने हिस्सा लिया। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को शामिल किया गया। सर्वे छात्रों के इंटरनेट यूजर्स पैटर्न पर आधारित था जिसमें सिक्मोमेट्रिक स्केल पर 15 अलग-अलग आइटम या कैटेगरी में छात्रों के इंटरनेट पर बिताए गए समय व पैटर्न पर उनको रेट किया गया। अगर स्कोर 60 के ऊपर है तो छात्र पीआईयू यानी प्रोब्लेमेटिक इंटरनेट यूजर है। सर्वे के मुताबिक 19 फीसदी छात्रों के 60 के ऊपर स्कोर मिले जो कि बेहद चिंता का विषय है। जहां एक तरफ ये आंकड़े दूसरे एशियाई देशों के बराबर हैं वहीं उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों से कहीं ज्यादा है। दिल्ली पुलिस और एम्स की संयुक्त टीम की अगर माने तो दिल्ली में ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि 22 फीसदी छात्रों ने

इंटरनेट पर बिताए गए समय की सही जानकारी नहीं दी। वर्तमान दौर में सोशल मीडिया से बच्चे और किशोर न सिर्फ तेजी से जुड़ रहे हैं बल्कि इसकी लत के शिकार हो रहे हैं। इसी डिजिटल लत से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया व अल्जीरिया सहित कई देशों में कर्तौनिक खोले गए हैं। अपने देश के भी वेंगलुरु और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में इंटरनेट डी-एडिक्शन खोले जा रहे हैं। दरअसल, आज देश ही नहीं, दुनिया भर में इंटरनेट की लत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस लत को कम करने के लिए ही दुनियाभर में इंटरनेट डी-एडिक्शन सेंटरों की जरूरत महसूस की जा रही है। इन डी-एडिक्शन सेंटरों पर जिंदगी को ऑफलाइन बनाने पर काम किया जाता है। डिजिटल लत की वजह से लोग अपनी वास्तविक समस्याओं से अब कट रहे हैं, मौलिक चिंतन और मौलिक सोच कम हो रहा है साथ ही लोगों का सामाजिक दायर भी कम हो रहा है। इंटरनेट एडिक्शन एक ऐसी मनोस्थिति है, जब लोग घंटों ऑनलाइन गेम, नेट सर्फिंग या सोशल साइट्स पर समय बिताने लाते हैं और कोई समय-सीमा नहीं रखते। खाद पर नियंत्रण कम होता जाता है। इंटरनेट नहीं मिलता, तो अधीर, बेचैन या अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। यहां तक कि झूठ बोलने,

समस्याओं से भागने लगते हैं और जल्द ही नकारात्मक तक हो जाते हैं। असल में युवा वर्ग सूचनाओं के बोज़ से दबा जा रहा है और उसके खुद के सोचने और समझने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है साथ ही काम में मौलिकता की आभाय स्पष्ट रूप से दिख रही है। मशहूर लेखक निकोलस कार ने मानव-मस्तिष्क पर इंटरनेट के प्रभाव विषय पर अपनी एक चर्चित पुस्तक 'द शैलोज' में कहा है, इंटरनेट हमें सनकी बनाता है, हमें तनावग्रस्त करता है, हमें उस ओर ले जाता है जहां हम इस पर ही निर्भर हो जाए। बिना मोबाइल या फोन के एक पुरा दिन बिताते की कल्पना अब बहुत मुश्किल लगती है, कुछ के लिए तो शायद असंभव! लेकिन हाल में ही पोलैंड वासियों ने डे विदाआउट सेल फोन अभियान के तहत अपना पूरा दिन बिना मोबाइल के ही बिताया। वहां लोगों को वास्तविक दुनिया से परिचित कराने और फोन पर संश्लेष के आदान-प्रदान की जगह आमने-सामने बैठकर रिश्तेदारों व दोस्तों से बात करने का मौका देने के लिए ही डे विदाआउट सेल फोन अभियान चलाया गया। यह अभियान पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है और इसमें पोलैंड वासी खूब रुचि दिखा रहे हैं।

असल में पोलैंड के ज्यादातर युवा क्लासरूम के साथ-साथ खाना खाते और सिनेमा देखते वक्त भी फोन का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से देश में फोनोलिज्म यानी फोन की लत की बीमारी में इजाफा हुआ है, ऐसे में इस तरह के अभियान की जरूरत पड़ती गई। आज के समय में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि युवाओं के अलावा कम उम्र के बच्चे भी अब डिजिटल लत के शिकार हो रहे हैं। वैसे तो साइबर एडिक्शन की समस्या पूरी दुनिया में फैली है लेकिन दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह समस्या ज्यादा गंभीर है। और अब समय आ गया है कि जब इसका समाधान तलाशा जाए नहीं तो यही मानव इतिहास सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित होगा। कुल मिलाकर साइबर एडिक्शन की लत से छुटकारा पाने के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक और परिवार के स्तर पर पहले परिश्रम होगी जिसमें हमें यह पलना होगा कि छोटें बच्चों को घर और स्कूल में मोबाइल फोन से दूर रखा जाए साथ ही भारत में भी डे विदाआउट सेल फोन जैसे अभियान चलाने की जरूरत है। वैसे यह तभी हो पाएगा, जब बड़े अपनी लत को छोड़ें, बच्चे उन्हीं को देखकर ही सीखेंगे।

शशांक द्विवेदी  
(वरिष्ठ पत्रकार)

## ट्विटर



अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह इंटरनेट फेलियर था या नहीं, किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच पूरी होने तक एक्शन नहीं लिया जाएगा। पुलिस पर सवाल गलत है।

आनंद कुमार एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर

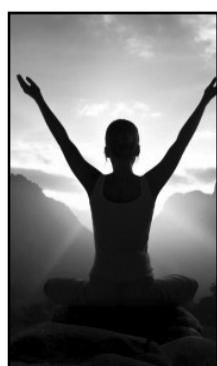
हिंसा के दौरान अराजकता, आमजनी, तोड़फोड़ तथा कोतवाल समेत दो की मौत के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को गलत नीतियों जिम्मेदार हैं। लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।

मायावती, बसपा प्रमुख



## सत्यार्थ

एक बार राजा चंद्रगुप्त तीर्थान्त के लिए काशी जा रहे थे। रात होने पर उन्होंने किसी भी नगर के भव्य भवन में ठहरने की अपेक्षा वन से रुकना उचित समझा। वह आम के एक उपवन में ठहरे। भोजन और विश्राम आदि की व्यवस्था की गई। कुछ संन्यासियों की रत चंद्रगुप्त अचानक बीमार हो गए। वैद्यों के उपचार ने उन्हें स्वस्थ तो कर दिया, मगर वे इसके बाद चिंता में डूब गए। विश्राम करने लगे कि वन और उसके आसपास रहने वाले आश्रमावासी और गांव के



का निवारण करते हुए कहा- भविष्य में भी शायद ही कोई आपके पास चिकित्सा के लिए

## अच्छे स्वास्थ्य का राज

लोग किस तरह रहते होंगे। उनके उपचार के लिए उन्होंने एक वैद्य को उस क्षेत्र में स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया। लेकिन वैद्य के काफी समय रहने के बाद ही जब कोई मरीज अपनी चिकित्सा कराने नहीं आया, तो उकता कर एक दिन वैद्य ने एक आचार्य से कहा-लगता है, मैं यहां व्यर्थ ही रह रहा हूँ। यहां के लोग अस्वस्थ नहीं होते अथवा मेरे पास उपचार कराने में संकोच करते हैं। तब आचार्य ने वैद्य की शंका को निवारण करते हुए कहा- भविष्य में भी शायद ही कोई आपके पास चिकित्सा के लिए

आए, क्योंकि यहां का प्रत्येक निवासी श्रम करता है। उसे जब तक भूख परेशान नहीं करती है, वह भोजन नहीं करता है। यहां सब अल्पभोजी भी हैं। आचार्य ने अपना आशय स्पष्ट करते हुए आगे कहा- भूख से कम भोजन हो और नीति-नियमों से अर्जित धन से जुटया आहार, तो बीमारी नहीं होती है। स्वस्थ रहने के लिए परिश्रम करना व परीना बहाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पवित्र मन भी आवश्यक है। अपवित्र मन वाला व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता। चंद्रगुप्त के पास इन तीन में से एक भी गुण नहीं था। इसलिए ही वे बीमार हुए। यहां की जनता बीमार नहीं होती।

जयगोपाल शर्मा

सार समाचार

**सैंटिनल आदिवासियों के हाथों मारा गया था अमेरिकी नागरिक**

पोर्ट ब्लेयर। अंडमान में पिछले महीने सैंटिनल आदिवासियों के हाथों मारा गया अमेरिकी नागरिक वहां सुनियोजित रोमांचक यात्रा पर गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के प्रमुख नंदकुमार साई ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर सैंटिनल जैसी कई आदिम जनजातियां हैं जिनसे बाहरी लोगों के संपर्क करने पर पाबंदी है। उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच से ऐसा लगता है कि अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाऊ वहां सुनियोजित रोमांचक यात्रा पर गया था। उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है। उत्तरी सैंटिनल द्वीप पर संरक्षित तथा एकांतवासी आदिवासियों ने 27 वर्षीय चाऊ की हत्या कर दी थी। चाऊ कुछ मछुआओं की मदद से वहां पहुंचे थे। उत्तरी सैंटिनल द्वीप पर जाने पर पाबंदी है। साई ने बताया कि चाऊ की यात्रा में मदद करने वाले लोगों की पहचान की कोशिश जारी है। इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, 'इन द्वीपों पर रहने वाले आदिम जनजाति के लोगों पर विदेशी नागरिकों की हमेशा से नजर रही है और उन्होंने पहले भी जनजातीय लोगों से संपर्क करने के प्रयास किए हैं। हमें इन जनजातियों के लोगों की सुरक्षा करने और उनके रहने के स्थान को बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह बंद करने की जरूरत है।'

**न्यू कैलेडोनिया 7.5 की तीव्रता वाला भूकम्प, सुनामी अलर्ट जारी**

सिडनी। न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप के पास 7.5 की तीव्रता वाला भूकम्प का शक्तिशाली झटका आने के बाद इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी भूकम्पविज्ञानियों ने यह जानकारी दी। प्रशांत सुनामी चेतावनी केन्द्र ने कहा, 'प्राथमिक भूकम्प तीव्रता पैमाने के आधार पर भूकम्प के केन्द्र से 1000 किलोमीटर के दायरे में स्थित तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें उठने की आशंका है।' न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने भी भूकम्प के बाद ऐसी ही चेतावनी जारी की है। भूकंप धरती की सतह से महज 10 किलोमीटर नीचे आया है। यूएसजीएस ने पहले भूकम्प की तीव्रता 7.6 बताई थी, जिसे बाद में 7.5 कर दिया।

**अमेरिका ने यूनान से ईरान के मिसाइल परीक्षण की**

आलोचना करने की अपील की संयुक्त राष्ट्र। अमेरिका ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करने के लिए आलोचना करने की अपील की। अमेरिका ने ईरान के इस कदम को खतरनाक बताया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करार दिया। फ्रांस और ब्रिटेन के आग्रह पर बंद दरवाजे के भीतर परिषद की बैठक हुई जिसमें अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका के साथ ही फ्रांस और ब्रिटेन ने भी ईरान पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शनिवार को करने का आरोप लगाया है। फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि ईरान का यह परीक्षण संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक अनुचित है। अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने एक बयान में कहा, 'ईरान का हालिया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण बेहद खतरनाक और चिंताजनक है लेकिन चौकाने वाला नहीं है।'

**अमेरिकी कमांडर ने खोली पोल कहा- पाकिस्तान का मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना**

**वॉशिंगटन (एजेंसी)**

अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर ने इस बात पर रोष जताया कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादी गुटों को सुरक्षित पनाहाह नहीं बनाने देने की दिशा में ठोस कदम उठाने में विफल रहा है। साथ ही उन्होंने सांसदों को बताया कि पाकिस्तान लगातार अफगान तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। मरीन कोर के लैफ्टिनेंट जनरल केनेथ मैकेजी का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफगानिस्तान शांति वार्ता में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मदद मांगे जाने के कुछ दिनों बाद आया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के अफगानिस्तान में चले सबसे लंबे युद्ध के बाद बातचीत के जरिए कोई हल निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

इस युद्ध में अमेरिका के 2,400 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। अर तालिबान अमेरिका नीत अंतरराष्ट्रीय बलों को देश

से भगाने और फिर से अपना शासन स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैकेजी ने यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर (सेंटकॉम) पद पर नियुक्ति के लिए सुनवाई के दौरान सीनेट को सस्त्र सेवा समिति से कहा, 'अफगानिस्तान में दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए पाकिस्तान अनिवार्य तत्व है।'

उन्होंने कहा कि तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, 'मैं उस प्रगति का स्वागत करूंगा। हालांकि, इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि तालिबान को वार्ता की मेज तक लाने में पाकिस्तान अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल कर रहा है।' मैकेजी ने सुनवाई के दौरान कहा, 'हम लगातार देखते आ रहे हैं कि स्थायी तथा सामंजस्यपूर्ण अफगानिस्तान का हिस्सा बनने की बजाए तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है।'

मैकेजी का यह जवाब ऐसे वक्त आया है जब ट्रंप ने हाल ही में इमरान को पत्र लिख कर अफगान शांति वार्ता में मदद मांगी है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री खान को एक पत्र भेजा है जिसमें अमेरिका नीत अफगान शांति प्रक्रिया तथा विशेष प्रतिनिधि जलमय खलौलजाद की क्षेत्र में होने वाली यात्रा में पाकिस्तान का पूरा सहयोग मांगा गया है।

उन्होंने कहा, 'पत्र में राष्ट्रपति ने कहा है कि पाकिस्तान में क्षमता है कि वह अपनी जमीन को तालिबान का सुरक्षित पनाहाह नहीं बनाने दे।' मैकेजी ने सांसदों से कहा कि वह अफगानिस्तान के प्रति अथवा आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के रखे हैं कोई खास परिवर्तन नहीं देखते। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया गणनीति पर पाकिस्तान के सकारात्मक रवैए के बावजूद हिंसक कट्टरपंथी संगठन अफगानिस्तान की सीमा से लगते उसके

क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिर सरकार पाकिस्तान के दीर्घकालिक हित में है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमय खलौलजाद ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मंगलवार को इस्लामाबाद में मुलाकात की। मैकेजी ने बताया कि यह बैठक आगे का रास्ता तलाशने के लिए थी। कोई भी समझौता किसी प्रकार के सहयोग अथवा पाकिस्तान के बिना होना मुश्किल है। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान इस बात से वाकिफ है कि अफगानिस्तान में किसी नतीजे के लिए उसके सहयोग की आवश्यकता होगी। मेरा मानना है कि हमें इस काम को इतना आकर्षक बनाना है जिससे उन्हें लगे कि ऐसा करना उसके सर्वश्रेष्ठ हित में है।' उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों को वापस बुलाने की समयसीमा पर कुछ भी बोलने से इनकार किया।



**वैश्विक संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, कहा- 'हर 70वें आदमी को है मदद की जरूरत'**

**संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)**

संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख ने कहा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों ने लाखों लोगों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। साथ ही उन्होंने 40 से अधिक देशों में अगले साल अत्यावश्यक राहत परियोजनाओं में सहयोग की खातिर कोष जुटाने की अपील भी की। यह कोष 25 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। वैश्विक मानवीय आवश्यकता के सालाना विश्लेषण जारी किए जाने के मौके पर, आपदा राहत समन्वयक मार्क लोकांक ने कहा कि विश्व भर में 40 से अधिक देशों में चल रहे संघर्षों को देखते हुये अगले साल 13 करोड़ से अधिक लोगों को मदद पहुंचाये जाने की आवश्यकता होगी। यानी मोटे तौर पर दुनिया के हर 70वें

व्यक्ति को मानवीय सहायता देनी होगी। उन्होंने कहा कि संघर्षों के साथ साथ मौसम में आ रहे बदलावों की वजह से पड़ने वाले सूखे और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकांक ने कहा कि दुनिया के हर 70 में से एक आदमी को संकटों का सामना करना पड़ रहा है और उसे तुरत ही मानवीय मदद और संरक्षण देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं जिसका मुख्य कारण संघर्ष है। विस्थापितों की संख्या लगभग सात करोड़ है। यह स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मानवीय सहायता अपील साल 2019 में 21.9 अरब डॉलर है। लेकिन अगर इसमें सीरिया की वित्तीय मदद जोड़ लिये जाते हैं तो यह राशि 25 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।



**अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी, कहा- 60 दिन के अंदर अपनी मिसाइलों को नष्ट करो, वरना...**

**इस्लामाबाद (एजेंसी)**

मॉस्को-रूस ने अमेरिका के उन दावों को खारिज किया है कि मॉस्को शीत युद्ध के दौरान हुए अहम परमाणु हथियार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखोरोवा ने कहा कि आधातहीन आरोप फिर से दोहराए जा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि रूस 'इंटरमीडिएट रेंज

न्यूक्लियर फोर्स' (आईएनएफ) संधि का उल्लंघन कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा, 'अमेरिका के इस रुख के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं पेश किया गया है।' उन्होंने इस संधि को वैश्विक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की आधारशिला बताया। इस बीच क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है ताकि संधि से हटने के अमेरिका के वास्तविक लक्ष्यों का पता नहीं चले। इससे पहले पोम्पियो ने मंगलवार को नाटो देशों के

विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में कहा था कि अगर रूस ने अपनी मिसाइलों को नष्ट नहीं किया तो अमेरिका 60 दिन के भीतर परमाणु हथियारों को लेकर हुई महत्वपूर्ण संधि से खुद को अलग कर लेगा। नाटो ने कहा कि अब संधि को बचाने का दोरोमदार रूस पर है। गौरतलब है कि अक्टूबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका संधि से अलग हो जाएगा और परमाणु हथियारों का जखीरा खड़ा करेगा।

**इकाडोर की उपराष्ट्रपति ने रिश्ततखोरी के आरोपों के बीच इस्तीफा दिया**

**किटो (एजेंसी)**



इकाडोर की उपराष्ट्रपति मारिया एलेजेंड्रा विकुना ने रिश्ततखोरी के आरोप लगने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। उनपर एक पूर्व सहयोगी ने रिश्तत लेने का आरोप लगाया था। यह मामला उस समय का है जब वह सांसद थीं। विकुना ने टिक्वटर पर गुरुवार को पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दक्षिण अमेरिकी देश को इस संकट के कारण 'अस्थिरता' में नहीं झोका जाना चाहिये। उन्होंने यह घोषणा राष्ट्रपति लैनिन मोरोने के उनसे दूरी बनाने और उन्हें पद से निलंबित करके उन्हें आरोपों का मुकाबला करने के लिये वक देने के बाद की। इकाडोर में उपराष्ट्रपति को नेशनल असंबली में सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के जरिये ही बर्खास्त किया जा सकता है। नेशनल असंबली ने पिछले सप्ताह उनसे इस्तीफा देने को कहा था। विकुना सिर्फ एक साल से इस पद पर थीं। उन्होंने मोरोने द्वारा नियुक्त उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लॉस की जगह ली थी। ग्लॉस को ओडोब्रेख्ट रिश्तत घोटाला मामले में सल्लिता के लिये दोषी ठहराये जाने के बाद जेल भेजा गया था। विकुना के खिलाफ आरोप उनके पूर्व सहयोगी एंजेल सेंगेबे ने लगाये हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि विकुना के सलाहकार के रूप में काम करने के दौरान उन्होंने नियमित रूप से विकुना के बैंक खाते में 2012 और 2013 के बीच धन जमा कराए। यह राशि कुल 20 हजार डॉलर है। उनका दावा है कि यह रकम रिश्तत के रूप में हासिल की गई थी। अभियोजक विकुना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि वह अदालत से बरी होंगी।

**अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन 2020 में लड़ सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव**



**वॉशिंगटन (एजेंसी)**

उन्होंने कहा, 'देश आज जिन परेशानियों का सामना कर रहा है, उन पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है, जिसमें मध्यम वर्ग की दुश्शा और विदेश नीति जैसे विषय शामिल हैं।' बराक ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार में उपराष्ट्रपति रह चुके बाइडेन ने कहा कि वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले अपने परिवार से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह अगले डेढ़-दो महीने में चुनाव लड़ने पर फैसला करेंगे। 'प्राइमस मी, डैड' ब्रेन कैम्पर से मा गए उनके पुत्र वियू के बारे में है। एक स्थानीय समाचार पत्र मिसोला कर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा, 'मैं समझता हूँ कि मैं देश का राष्ट्रपति बनने के लिये सबसे योग्य व्यक्ति हूँ।'

**सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सिरफिरे, सनकी और खतरनाक हैं, जानें ऐसा किसने और क्यों कहा**



**2004 में लोकसभा चुनाव जीत जाती बीजेपी, तो सुलझ जाता कश्मीर मुद्दा- इमरान खान**

**वॉशिंगटन (एजेंसी)**

अमेरिकी सीनेटर्स का कहना है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए की जानकारी के बाद यह अधिक स्पष्ट हो गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की पत्रकार जमात खशागी की हत्या में भूमिका थी। बीबीसी के मुताबिक, सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जमाल खशागी की हत्या में हाथ है। उन्होंने कहा कि सऊदी सरकार को हथियारों की बिक्री का साउथ कैरोलाना से सीनेटर लिंडसे ने कहा कि

कहा कि दो परमाणु संपन्न देश लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि, 'इसके गंभीर परिणाम होते हैं।' **पड़ोसी मुल्कों से शांतिपूर्ण रिश्ते का पक्षधर है पाकिस्तान-खान**

इमरान खान ने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते बनाने के पक्षधर है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहां पर आम चुनाव होना है। अमेरिका समेत विदेश नीति को लेकर सेना की भूमिका पर उनके विचारों के बारे में जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब भी सुरक्षा का मामला शामिल होता है तो उसमें उनसे सलाह ली जाती है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान में सेना, सरकार सभी एक साथ हैं और उनके फैसले को मिलिट्री का समर्थन मिला हुआ है।

भी यही राय थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को बात को सुनने के बाद तो यही लगता है कि कश्मीर समस्या के समाधान को लेकर दोनों देश काफी करीब थे। इमरान खान ने कहा कि बिना बातचीत के कश्मीर पर किसी तरह के समाधान के विकल्प पर चर्चा नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ही निकाल सकते थे। **कश्मीर समस्या के हल के लिए दो-तीन विकल्प!** जब खान ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए फॉर्मूला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके दो तीन विकल्प हैं जिन पर चर्चा होनी है। हालांकि, उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि इस बारे में ज्यादा बताना अभी काफी जटिल है। भारत के साथ संभावित किसी युद्ध की संभावना को खारिज करते हुए उन्होंने



